

[SMT. MIRA DAS]

There is seepage on the body of the Temple. There is no coordination between the organisations which are providing the chemicals for the repair and the preservation of the Temple premises. The State Government has nothing to do with the preservation of the Temple as a temple structure. But the State Government, under the leadership of Shri Biju Patnaik, is almost prepared to provide necessary help and co-operation to the Archaeological Survey of India.

On the 29th November, three deities of Jagannath, Balabhadra and Subhadra have been shifted to a different place inside the Temple for facilitating the repair work. I urge upon the Minister of Human Resource Development to ensure that the repair work is finished within the specified time-limit. I hope the Indian Archaeological Department will take the opinion of experts and also the opinion of eminent archaeologists before starting the repair work of the Temple. Thank you.

श्री भोजेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष जी, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

Discontentment among youth due to deletion of Arabic, Persian and Pali Languages from Optional Subjects for Civil Services (Main) Examination

मौलाना ओबैदुल्ला खान अजमी (उत्तर प्रदेश) : मुकिया वाइस चैयरमैन साहब, मैं सबसे पहले वाइस चैयरमैन की हैसियत से कुरसी हकदारत पर आपके इंतज़ाब के लिए आपको मुबारकवाद पेश करता हूँ और उसके बाद आपकी इस हुकूमते हिंद का ध्यान यूनिवर्स पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से अरबी, फारसी और पाली जुबानों के साथ होने वाली नाइंसाफी की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ।

मोहतरम वाइस चैयरमैन साहब, यूनिवर्स पब्लिक सर्विस कमिशन में घुसे हुए फिरकापरस्त और आला ओहदेदारान/अकलिखत गुपमन अमातिर ने अरबी, फारसी और पाली को इंतहानात के

अख्तियारी मजामीन की फेहरिस्त से खारिज करने का काम करके इन तीनों जुबानों से अपनी बंदी जेहनियत का सबूत दिया है और यह सारा कारोबार हिंदुस्तान की धरती पर मुस्लिम तहजीबी और शकाफती निशानियों को जड़ से उखाड़ने की खाइश रखने वाले अपने आकाशों के इशारों पर नाश्ते हुए मुल्क में फिरकापरस्ती का जहर फैलाने वालों का हीसला बढ़ाने की एक नापाक कोशिश की है ताकि हिन्दुस्तानी मुसलमान अपने मुल्क की तरक्की और अपनी खुशहाली का काम करने के बजाय निचली सतह के मसाइल ही में उलझे रहें। मैं बहुत सफायी के साथ हुकूमते हिंद से कहना चाहूंगा कि अगर वजीरे आजम, वजीरे दाखिला, वजीरे तालीम और वजीरे फलाहोबहवूद और हुकूमते हिंद के दूसरे जिम्मेदारों ने फौरी तौर पर इस तरफ तबज्जो देकर फिरकापरस्ती की इस साजिश को नाकाम नहीं बनाया तो पूरे मुल्क में इस तरह वह बेचैनी का एक तूफान खड़ा होगा जिससे मुल्क की जहूरियत और हुकूमते हिंद के सेकुलर के किरदार पर भी एक सवालिया निशान लग जाएगा।

मोहतरम वाइस-चैयरमैन साहब, यूनिवर्स पब्लिक सर्विस कमिशन की धांधली और नाइंसाफी की पोलपट्टी डा० सतीश चन्द्रा कमेटी की रिपोर्ट से खुल जाती है। चूंकि मुल्क में यह मसला एक हैरानी और तूफानी बन गया है, इस लिए मैं हाऊस के जरिए इस मसले पर हुकूमते-हिंद से भरपूर इंसफ चाहता हूँ। यूनिवर्स पब्लिक सर्विस कमिशन ने अगस्त, 1988 में सिविल सर्विसेज के इम्तिहान की स्कीम का जायजा लेने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स के साबिक चैयरमैन डा० सतीश चन्द्रा के तहत एक खुसूसी कमेटी की तसकील की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी हुकूमते-हिंद को बाध

में पेश कर दी, लेकिन तीन साल का अरसा गुजर जाने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ने इस बात को ज़रूरत महसूस की कि इसके करारदातों के सिलसिले में लाजमी तौर पर कोई फ़ैसला लिया जाए। मज़कूरा बाला फ़ैसला जो अरबी, परसियन और पाली जुबां को अख़्तियारी मजमून की हैसियत से खारिज कर देने का है। यह इसी कमेटी के फ़ैसले की रोशनी में किया गया। मगर, सदे मोहतरम, इस सिलसिले में दिवचस्प बात यह है कि डॉ. चन्द्रा कमेटी में 6 सदस्यों कमेटी बनी थी, जिसके 6 मेम्बरन थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ने हालिया फ़ैसले पर अपनी बेइतमिननी का इन्हें किया है। उन मेम्बरन में टी. ओ. सतीश चन्द्रा एस. एन. मधुर, ड. के. वैक्टरमैय, डा. फ्रांसिस एम. एम. सर, सी. एम. स्वामीनाथन और डी. पी. पाजी पेश-पेश हैं। इस कमेटी के चेयरमैन डा. सतीश चन्द्रा और सेक्रेटरी बी. सी. होता हैं। इन अरकाने कमेटी ने एहतज़ाज करते हुए यह कहा है, इनकी कमेटी ने सिर्फ़ चार गैर-मुल्की जुबानों फ़्रांसीसी, जर्मनी, रूसी और चीनी जुबानों को खारिज करने की सिफारिश की थी क्योंकि सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में इन चार जुबानों में बहुत कम तलबा पाए जाते हैं, लेकिन हुकूमत ने अरबी, फारसी और पाली को भी इसमें शामिल कर लिया।

मोहतरम वाइस-चेयरमैन साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि एक कमेटी बनी जुबानों का सर्वे करने के लिए और जुबानों का सर्वे करके जब उस कमेटी ने हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि चार जुबानों को गैर-मुल्की हैसियत से खारिज कर दिया जाए, उन जुबानों में तलबा ही बहुत कम है। तो उन चार जुबानों के लिए तो रिकवेस्ट की थी, मगर तीन जुबानों को फिरकापरस्तों ने और

एड करके हिन्दुस्तान की सकाफ़त, हिन्दुस्तान की तहज़ीब, हिन्दुस्तान के तमदुन और हिन्दुस्तान की तारीखी-बरासत का बड़ा भयंकर खून किया। कमेटी के अरकान का यह कहना है कि अरबी, फारसी और पाली, यह हमारे मुल्क की बहम जुबानें हैं और मुल्क की तहज़ीब का असास है, इसलिए इन्हें गैर-मुल्की जुबानों के साथ हरगिज नहीं जोड़ा जा सकता। अरकाने कमेटी का यह भी कहना है कि अगर कोई तलब की बुनिवाद पर संस्कृत को बरकरार रखा जा सकता है तो फिर कोई बाह नहीं है कि अरबी, फारसी और पाली का इतना मुल्क में तालोमी इबारों का बंद कर दिया जाए।

मोहतरम वाइस-चेयरमैन साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि एक कमेटी बनाई गई कि वह जुबानों का जायजा ले। उस कमेटी ने जुबानों का जायजा लेकर चार जुबानों को खारिज करने का मुताअबा किया, मगर कमेटी के इस मुताअब के बाद तीन जुबानों को अपनी तरफ से एड करके खारिज किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की धांधली और बेइमानी करके क्या हिन्दुस्तान में रहने वाली माइनों-रिटी की तहज़ीबों तमदुन गारत करने की बहनापाक साजिश नहीं है? अरबी और फारसी का हिन्दुस्तान की आजादी से कितना गहरा ताल्लुक, मोहतरम वाइस-चेयरमैन साहब, रहा है? इसे आप भी जानते हैं और हिन्दुस्तान का हर पढ़ा-लिखा इंसान अच्छी तरह से जानता है। रेशमी रुमाल तहरीक रही हो या बाकसोर तहरीक रही हो या खुदाई खिदमतगार तहरीक रही हो या हिन्दुस्तान में मजलिस एहदार तहरीक रही हो या खिलाफत कमेटी तहरीक रही हो या मौलाना अबुल कलाम आजाद की बाथरेक्ट कमेटी तहरीक रही हो, हिन्दुस्तान की आजादी के सिलसिले में इन तमाम तरबेमाहों ने

[मौजाना ओबैदुल्ला खान आखमी]

अपना खूने-जिगर बढ़ाकर भारत की मांग में आजादी का सिन्दूर रचा और बसा दिया। मैं कहना यह चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान सरजमीं पर कितने ही वर्ष तक कमोवेश फारसी का चसन रहा है, आज भी हमारी अदालतों में फारसी जुबां की परंपरा जारी सारी है। अरबिक के यूनिवर्सल प्रोग्रामात, अरबिक मजामीन, इलाहाबाद बोर्ड से मालिम और फाजिल के अरबिक के सर्टिफिकेट, हिन्दुस्तान में करोड़ों-करोड़ों मुसलमान अरबी पढ़ते हैं, अरबी में उसका मजहब, अरबी में उसकी मजहबी किताब, अरबी में उसकी इबादत, अरबी में उसकी नमाज-रोजा, अरबी में उसके हज और जकात, इन तमाम तरतहजीबी रिवायतों को गाररुत करने की यह तहरीक चलाई जा रही है। जिसके खिलाफ मैं जवदेस्त मजहमत करते हुए हुकूमते-हिन्द से डिमांड करता हूँ कि अरबी, फारसी और पाली, जो कतई इस मुल्क की जुबानें बन गई हैं और इन जबानों का भरपूर हिस्सा रहा है इस मुल्क की तरबीज-ओ-तरक्की में, उन जबानों को इन इम्तहानात् में शामिल किया जाए और कमेटी के इन तमामतर वाजिब, जायज मुतालबात को पूरा किया जाए जिसमें खुद कमेटी के अरकान ने इन जुबानों को हिन्दुस्तानी जबान से ताबीर किया है। आज हिन्दुस्तान में करोड़ों रुपए की लाइब्रेरी अरबी की हैं, परशियन की हैं। इन जबानों की ये लाइब्रेरियां खत्म हो जाएंगी, बेमकसद हो जाएंगी, जब इन जुबानों के जरिए इम्ताहन में तलबा को नहीं बैठने नहीं दिया जाएगा। पूरे हिन्दुस्तान का कमोवेश में दौरा करता हूँ, मुझे हर जगह मुसलमानों में खुसूसियत के साथ बेचैनी और इस्तराब की लहरें देखने को मिली हैं, जगह-जगह लोगों में इसके खिलाफ गहरी तशबीष जाहिर की गई है। इसलिए मैं इस हाउस में अपनी इस जुबान के

तहफूस के लिए हुकूमते-हिन्द और हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आज परशियन में आमिर सुभानी, जिसने कि आल इंडिया आई. ए. एस. टॉप किया था, आमिर सुभानी का भी यही मजमून था। 90 यूनिवर्सिटियां हैं हिन्दुस्तान में जिनमें यह परशियन पढ़ी और लिखी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। अरबी, दुनियां के बेशतर भूमालिक में सरकारी जुबान है। हमारे मुल्क का अरबी जुबान से कितना ताल्लुक है। आज लाखों वकंर हमारे हिन्दुस्तान का अरब भूमालिक में जाकर रुपया कमाता है और हिन्दुस्तान को फारेन एक्सचेंज देता है। अरबी न जानने की बिना पर उसकी तनख्वाह में भी कटौती होती है, उसके आमदनी के जराए भी बंद हो जाते हैं, मगर इस जुबान के हासिल करने के बाद वह हिन्दुस्तान के फरोग का सामान बनत है। पांच नव-आजाद जम्हूरियाओं में, रशिया में जो हुकूमतें कायम हुई हैं, उनमें भी उन पांचों हुकूमतों की सरकारी जुबान फारसी है, ईरान की भी सरकारी जुबान फारसी है। इन जुबानों के साथ पिछले दौर में हमारा कितना गहरा ताल्लुक रहा है, हम इस बात को जानते हैं। सदरे जम्हूरिया अरबी में भी लोगों को ईनाम देने के लिए, परशियन में भी लोगों को ईनाम देते हैं। इन तमाम चीजों को मदेनजर रखते हुए फारसी के तलबा की भी कमी नहीं है, अरबी के स्टूडेंट्स की भी कमी नहीं है। अब जरा मसलमानों में जब थोड़ी तालीमी बेदारी आई है, तो तालीमी बेदारी का यह घिनीना मज्राक किया जा रहा है। जिस रास्ते से मुसलमान तरक्की करने की कोशिश करता है, वह रास्ता उस पर

जान-बूझकर के बंद कर दिया जाता है। तो खुदा के लिए, एक तरफ तो यह इल्जाम लगाते हैं हुकूमत के अरकान, एक तरफ हमसे कहा जाता है कि मुसलमान पढ़ता-लिखता नहीं है और जब मुसलमान पढ़ने-लिखने की राह पर लग जाता है तो पढ़ने-लिखने के रास्ते काट दिए जाते हैं, उसकी तरक्की का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि ये जुबानें हमेशा हमारे मुल्क की शान, आन, बान रही हैं। हमारे मुल्क की विरासत के साथ, हमारे मुल्क की तहजीब-ओ-तमददुन के साथ इन जुबानों का सीधा रिश्ता है। इसलिए इन जुबानों को यूनिपन पब्लिक सर्विस कमीशन की नाइंसाफियों के खिलाफ फिर से वह दर्जा मिलना चाहिए, जिसके जरिए बच्चे सिविल सर्विसिज के इम्तहानात में बैठते थे। साथ-साथ एक बात और अर्ज करूंगा।...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : Please try to conclude. There are two or three Members who want to associate with your special mention. Kindly bear their interest also in your mind.

मौलाना अबुलकुल्ला खान ब्राह्मी : बिल्कुल आखिरी बात कहना चाहता हूँ। एक सैकिड का मोका और चाहता हूँ सर। मैं कहना यह चाहता हूँ कि हर तरफ ही यह तमाशा हो रहा है। मुल्क से अरबी को खत्म कर कर दो, परसियन को खत्म कर दो। इस हाउस में दर्जन से ज्यादा लोग उर्दू में तकरीरें करते हैं। सिकन्दर बख्त साहब की भी जुबान निहायत शानदार और हमेशा उर्दू-ए-मुअल्ला को वे इस्तेमाल करते हैं। इस हाउस में पी० शिवशंकर के जरिए और सर, आप भी रहे होंगे, दूसरे मेम्बरान-ए-पार्लियामेंट के जरिए

हमने अपने साबिक चेयरमैन के सामने भी उर्दू का मसला रखा था कि एक मूतरज्जिम दे दिया जाए, एक इन्टरप्रेटर दे दिया जाए, मगर आज तक ये....

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिबते रज़ी) : यह उर्दू का मसला नहीं है।

मौलाना अबुलकुल्ला खान ब्राह्मी : नहीं, मैं कहना यह चाहता हूँ कि जहाँ-जहाँ भी हमारे हुक है, वहाँ-वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। आखिर यह घांघली कब तक चलती रहेगी ? मैं इस घांघली के खिलाफ जबर्दस्त मज्मूमत करते हुए अरबी, परसियन और पाली को फिर से उनकी बहाली की मांग करता हूँ ताकि मुल्क में मुसलमानों में और इंसान-मसल इंसानों में फैली हुई बेचैनी का खाला हो सके। बड़ी भारी मुसीबत तो यह है :—

“नहीं मिनतकशे तावे शुनीदम दास्तां मेरो, खामोशी गुफतगू है, बेजुबानी है, जुबां मेरी यह दस्तूरे जुबांवदी है कैसा तेरी महफिल में जहाँ पर बात करने को तरसती है जुबां मेरी उड़ाए कुछ बरक लाला ने, कुछ गुलामी ने, कुछ गुल ने खमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी शुक्रिया।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی :
”اگر پردیش، شکریہ وائس پیڑمین
صاحب میں سب سے پہلے ائس پیڑمین
کی حیثیت سے کوئی صدارت پر آئیے
انتخاب کے لئے آپ کو مبارکباد پیش
کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے درمیان
حکومت ہند کا دھیان برائین پر ہوگا

[मोहाना जोबेदल्ला खान आबमी]

سروس کمیشن کی طرف سے عربی فارسی اور پالی زبانوں کے ساتھ ہونے والی نا انصافی کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں محترم وائس چیئرمین صاحب یونین پبلک سروس کمیشن میں گھسے ہوئے فرقہ پرست اور اعلیٰ عہدیداران اقلیت دشمن عناصر نے عربی فارسی اور پالی کو امتحانات کے اختیاری مضامین کی فہرست سے خارج کرنے کا کام کر کے ان تینوں زبانوں سے اپنی گندی ذہنیت کا ثبوت دیا ہے اور یہ سارا کاروبار ہندوستان کی دھرتی پر مسلم تہذیب اور ثقافتی نشانیوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی خواہش رکھنے والے اپنے اکواؤں کے اشاروں پر ناچتے ہوئے ملک میں فرقہ پرستی کا زہر پھیلانے والوں کا حوصلہ بڑھانے کی ایک ناپاک کوشش کے تحت کیا گیا ہے تاکہ ہندوستانی مسلمان اپنے ملک کی ترقی اور اپنی خوشحالی کا کام کرنے کے بجائے نجلی سطح کے مسائل ہی میں الجھے رہیں۔ میں بہت صفائی کے ساتھ حکومت ہند سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر تعلیم اور وزیر فلاح و بہبود اور حکومت ہند کے دوسرے ذمہ داروں نے فوری طور پر اس طرف توجہ دے کر فرقہ پرستی کی اس

سازش کو ناکام نہیں بنایا تو پورے ملک میں زبردست جیمینی کا ایک طوفان کھڑا ہوگا جس سے ملک کی جمہوریت اور حکومت ہند کے سیکولر کردار پر بھی ایک سولہ نشان لگ جائے گا۔

محترم وائس چیئرمین صاحب یونین سروس کمیشن کی دھاندلی اور نا انصافی کی پولیٹی ڈاکٹر ستیش چندرا کمیٹی کی رپورٹ سے کھل جاتی ہے کیونکہ ملک میں یہ مسئلہ ایک سیمانی اور طوفانی بن گیا ہے۔ اس لئے میں ہاؤس کے ذریعہ اس مسئلہ پر حکومت ہند سے پورے انصاف چاہتا ہوں۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے اگست ۱۹۸۸ میں سول سروسز کے امتحان کی اسکیم کا جائزہ لینے کیلئے یونیورسٹی گرانٹس کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ستیش چندرا کے تحت ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ بھی حکومت ہند کو بعد میں پیش کر دی لیکن تین سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد یونین پبلک سروس کمیشن نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اس کی قراردادوں کے سلسلے میں لازمی طور پر کوئی فیصلہ لیا جائے مذکورہ بالا فیصلہ جو عربی پرشین اور پالی زبانوں کو عربی

اختیاری معنوں کی حیثیت سے خاویں
 کر دینے کا ہے۔ یہ اسی کمیٹی کے فیصلے
 کی روشنی میں کیا گیا۔ مگر صدر محترم
 اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ
 ڈاکٹر چندرا کی صدارت میں ۶ رکنی
 کمیٹی بنی تھی جس کے ۶ ممبران تھے۔
 یونین پبلک سروس کمیشن نے حالہ یہ
 فیصلہ پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا
 ہے۔ ان ممبران میں ٹی۔ اوستیش چندرا
 ایں۔ این ماقہرہ ڈاکٹر کے۔ وینکٹ رما
 ڈاکٹر خزانہ ایس ایم۔ ایم بی سی۔ ایس سوامی
 ناھن اور ڈی۔ پی۔ پاجی پیش پیش
 ہیں۔ اس کمیٹی کے چیئر مین ڈاکٹر ستیش
 چندرا اور میمبیر ٹی بی۔ سی۔ ہوتا ہیں
 ان اراکین کمیٹی نے احتجاج کرتے ہوئے
 یہ کہا ہے کہ ان کی کمیٹی سے چار غیر ملکی
 زبانوں۔ فرانسیسی۔ جرمنی اور روسی
 اور چینی زبانوں کو خارج کرنے کی
 سفارش کی تھی کیوں کہ سول سروس کے
 امتحانات میں ان چار زبانوں میں بہت
 کم طلبہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن یونین
 پبلک سروس کمیشن نے عربی۔ فارسی اور
 پالی کو بھی اس میں شامل کر لیا۔
 محترم وائس چیئر مین صاحب میں
 یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنی

زبانوں کا سروے کرنے کے لئے اور
 زبانوں کا سروے کر کے جب اس کمیٹی نے
 حکومت کو رپورٹ پیش کر دی کہ چار زبانوں
 کو غیر ملکی ہونے کے ناطے سے خارج کر
 دیا جائے۔ ان زبانوں میں طلبہ بھی بہت
 کم ہیں تو ان چار زبانوں کے لئے تو انہوں
 نے ریکریٹ کی تھی مگر تین زبانوں کو فرقہ
 پرستوں نے اور ایڈ کر کے ہندوستان کی
 ثقافت ہندوستان کی تہذیب ہندوستان
 کے تمدن اور ہندوستان کی تاریخی وراثت
 کا بڑا بھینکر خون کیا۔ کمیٹی کے ارکان کا یہ
 کہنا ہے عربی۔ فارسی اور پالی ہمارے
 ملک کی اہم زبانیں ہیں اور ملک کی
 تہذیب کا اثاثہ ہیں۔ اس لئے انہیں غیر
 ملکی زبانوں کے ساتھ ہرگز نہیں جوڑا جا
 سکتا۔ ارکان کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر
 چند طلبہ کی بنیاد پر سنسکرت کو برقرار رکھا
 جاسکتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ عربی
 فارسی اور پالی کا دروازہ ملک میں تعلیمی
 اداروں کا بند کر دیا جائے۔
 محترم وائس چیئر مین صاحب میں
 عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنائی
 گئی کہ وہ زبانوں کا جائزہ لے۔ اس کمیٹی
 نے زبانوں کا جائزہ لے کر چار زبانوں کو
 خارج کرنے کا مطالبہ کیا۔

[मौलाना औबेदुल्ला खान आजमी]

مکرمیٹی کے اس مطالبہ کے بعد تین زبانوں کو اپنی طرف سے ایڈ کر کے خارج کر دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی دھاندلی اور بے ایمانی کر کے کیا ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کو غارت کرنے کی یہ ناپاک سازش نہیں ہے۔ عربی اور فارسی کا ہندوستان کی آزادی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ محترم وائس چیمبرمین اسے آپ بھی جانتے ہیں اور ہندوستان کا ہر ٹپ چاکھا انسان اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ریشی رومال تحریک رہی ہو یا خاکسار تحریک رہی ہو یا خدائی خدمتگار تحریک رہی یا ہندوستان میں مجلس احرار تحریک رہی ہو یا خلافت کمیٹی تحریک رہی ہو یا مولانا ابولکلام آزاد کی ڈائریکٹ کانگریس کمیٹی تحریک رہی ہو۔ ہندوستان کی آزادی کے سلسلہ میں ان تمام ترجماعتوں نے اپنا خون جگر بڑھا کر بیدارت کی مانگ میں آزادی کا سندور رچا اور بسا دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر کتنے زمانے تک کم و بیش فارسی کا جلن رہا ہے۔ آج بھی بھاری عدالتوں میں فارسی زبان کی پریس جاری و ساری ہے۔ عربک کے یونیورسل پروگرامات عربک

مضامین۔ الہ آباد بورڈ سے عالم فاضل کے عربک سہ ماہی ٹیکسٹ۔ یہ سب ہم کاری طور پر جاری ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے کروڑوں کروڑ مسلمان عربی پڑھتے ہیں۔ عربی میں اس کا مذہب۔ عربی میں اس کی مذہبی کتاب عربی ہیں اس کی عبارت عربی میں اس کی نماز روزہ عربی میں اس کے حج زکوٰۃ۔ ان تمام تہذیبی مذہبی روایتوں کو غارت کرنے کی یہ تحریک چلاتی جا رہی ہے۔ جس کے خلاف زبردست مذمت کی جاتی ہے۔ حکومت ہند سے ڈیماڈ کرتا ہوں کہ عربی، فارسی اور پالی جو قطعی اس ملک کی زبانیں ہیں جو قطعی اس ملک کی زبانیں ہیں اور ان زبانوں کا تادیبی آزادی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ لہذا اس ملک کی ترقی و ترویج میں ان زبانوں کو ان امتحانات میں شامل کیا جائے۔ اور کمیٹی کے ان تمام تر واجب جانر مطالبات کو پورا کیا جائے جس میں خود کمیٹی کے ارکان نے ان زبانوں کو ہندوستانی زبان سے تعبیر کیا ہے۔ آج ہندوستان میں کروڑوں روپے کی لاٹری بری عربی کی ہے پرشین کی ہے۔ ان زبانوں کی یہ لاٹری بیاں ختم ہو جائیں گی۔ بے مقصد ہو جائیں گی جب ان زبانوں کے ذریعہ امتحان میں

طلبا کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ پورے
ہندوستان کا کم و بیش میں دورہ کرتا ہوں
مجھے ہر جگہ مسلمانوں میں خصوصیت کے
ساتھ بچپنی اور اضطراب کی لہریں دیکھنے
کو ملی ہیں۔ جگہ جگہ لوگوں میں اس کے
خلاف گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے۔
اس لئے میں اس باؤس میں اپنی اس
زبان کے تحفظ کے لئے حکومت ہند اور
باؤس کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔

سہ۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا
کہ پشین میں عامر سبحانی جس نے کہ آل
انڈیا آئی۔ اے۔ ایس۔ ٹاپ کیا تھا عامر
سبحانی کا بھی یہی مصنون تھا۔ ۱۰ یونیورسٹیاں
ہیں ہندوستان میں جن میں پشین پڑھی
اور ابھی جا رہی ہے۔ پڑھائی جا رہی ہے
عربی دنیا کے بیشتر ممالک کی سرکاری زبان
ہے۔ ہم اسے ملک کا عربی زبان سے کہتا
گہرا تعلق ہے۔ آج لاکھوں درکر ہمارے
ہندوستان کا عرب ممالک میں جا کر روپیہ
کما رہے اور ہندوستان کو فاران انجین
دیتا ہے عربی نہ جاننے کی بنا پر اس کی
تنخواہ میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے آمدنی
کے ذرائع بند ہوتے ہیں مگر اس زبان
کو حاصل کرنے کے بعد وہ ہندوستان کے
فروغ کا سامان بنتا ہے۔ پانچ نو آزاد

جمہوریاتوں میں۔ رشتا میں جو حکومتیں
قائم ہوئی ہیں۔ ان میں ان پانچوں حکومتوں
کی سرکاری زبان فارسی ہے۔ ایران کی بھی
سرکاری زبان فارسی ہے۔ ان زبانوں کے
ساتھ پچھلے دور میں ہمارا کتنا گہرا تعلق
رہا ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں صدر
جمہوریہ عربی مضافین میں بھی لوگوں کو
انعام دیتے ہیں۔ پرشین مضافین میں
بھی لوگوں کو انعام دیتے ہیں۔ ان تمام
چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فارسی کے
طلبا کی بھی کمی نہیں ہے۔ عربی کے سٹوڈنٹس
کی بھی کمی نہیں ہے۔ اب ذرا مسلمانوں
میں جب تھوڑی تعلیمی بیداری آئی ہے
تو تعلیمی بیداری کا یہ گھنڈا نامتناہی
کیا جا رہا ہے جس راستے سے مسلمان
ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ راستہ
اس پر جان بوجھ کر بند کر دیا جاتا ہے۔
تو خدا کے لئے بتا دیجئے۔ ایک طرف تو یہ
الزام لگاتے ہیں حکومت کے ارکان۔
ایک طرف ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ
مسلمان پڑھتا لکھتا نہیں ہے اور جب
مسلمان پڑھنے لکھنے کی راہ پر لگ جاتا
ہے۔ تو پڑھنے لکھنے کے راستے کاٹ
دیئے جاتے ہیں اس کی ترقی کا دروازہ
بند کر دیا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا

[मोना आबेदुल्ला खान आबमी]

ہوں کہ یہ زبانیں ہمیشہ ہمارے ملک کی شان آن۔ بان رہی ہیں۔ ہمارے ملک کی وراثت کے ساتھ ہمارے ملک کی تہذیب و تمدن کے ساتھ ان زبانوں کا سیدھا رشتہ ہے۔ اس لئے ان زبانوں کو یونین پیپک سرویس کمیشن کی نا اعلیٰ کے خلاف پھر سے وہ درجہ ملنا چاہیے جس کے ذریعہ مسلم بچے سول سرویس کمیشن کے امتحانات میں بیٹھتے تھے۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں گا۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : Please try to conclude. There are two or three Members who want to associate with your special mention. Kindly bear their interest also in your mind.

مولانا عبید خاں اعظمی، بالکل آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک سیکنڈ کا موقع اور چاہتا ہوں سر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر طرف ہی یہ تماشہ ہو رہا ہے ملک سے عربی کو ختم کر دینا اور عربی کو ختم کر دینا۔ اس بارے میں درجن سے زیادہ لوگ اردو میں تقریریں کرتے ہیں۔ سکندر رخت صاحب کی بھی زبان نہایت شاندار اور ہمیشہ اردو معلیٰ کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس بارے میں پی شو شکر صاحب کے ذریعے سر۔ آپ بھی ہے ہوں گے دیگر ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے ہم نے اپنے سابق چیئرمین کے سامنے بھی اردو کا

مسئلہ رکھا تھا کہ ایک مترجم دے دیا جائے مگر آج تک یہ۔۔۔

اپنا بھادھیکش: یہ اردو کا مسئلہ نہیں ہے

مولانا عبید خاں اعظمی: بہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہمارے حقوق ہیں۔ وہاں وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ آخر یہ دھاندلی کب تک چلتی رہے گی۔ میں اس دھاندلی کی زبردست مذمت کرتے ہوئے عربی پرشین اور پالی زبانوں کو پھر سے ان کی بحالی کی مانگ کرتا ہوں تاکہ ملک میں مسلمانوں میں اور انصاف پسند انسانوں میں پھیلی ہوئی بھیجی کا خاتمہ ہو سکے۔ بڑی بھاری مصیبت تو ہے یہ ہے۔

نہیں منست کش تا بہ شنیدن داستان میری خاموشی گفتگو ہے۔ بے زبانی ہے زبان میری یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری اڑھے کچھ ورق لالہ نے کچھ گل جین نے کچھ گل نے جن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری ختم شد

[6.00 P. M.]

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : If the House agrees, we can extend the sitting for another five minutes only. Otherwise, we do not have the time.

SOME HON. MEMBERS : Yes, we can sit for five minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : I request all the hon. Members who want to associate themselves with the special mention to conclude within five minutes.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ श्रीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : सर, मेरा कहना यह है कि यह बाकायदा एक साजिश है। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ जैसा कि सतीश चन्दा कमीशन की रिपोर्ट में इसके अन्दर इन तीनों जुवानों के नाम नहीं दिए गए हैं लेकिन इसमें शामिल कर लिया गया है, उसकी वजह खास तौर से क्या है ? यह तीनों जुवाने स्कोरींग मार्क्स देती है। अगर सबजेक्ट में लें तो इसके अन्दर काफी अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। और इसके जरिए से लोग सर्विस में आ जाते हैं। मौलाना साहब ने बहुत वजाहत से कह दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इन जुवानों को इससे निकालकर बाकायदा यह साजिश की गई है कि एक मखसूस कम्युनिटी के लोग जो इन जुवानों को जरा ज्यादा पढ़ते हैं वह लोग सर्विस में न आएँ। यह एक साजिश है और मैं मतालवा करता हूँ कि इसकी तहकीक करें और इन जुवानों को इसके अंदर वापिस लेकर आए और इसके अन्दर इख्तियारी मजामिन की इजाजत दी जाए।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل۔
سر۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک
سازش ہے۔ اس لئے میں یہ بتانا چاہتا
ہوں جیسا کہ سٹیش چندرا کمیشن کی
رپورٹ میں اس کے اندر ان تینوں
زبانوں کے نام نہیں دیئے گئے ہیں۔
لیکن اس میں متداخل کر لیا گیا ہے۔
اس کی وجہ خاص طور سے کیا ہے۔ یہ
تینوں زبانیں اسکوئنگ مارکس دیتی
ہیں۔ اگر سبجیکٹ میں لیں تو اس کے
اندر کافی اچھے مارکس ہو جاتے ہیں اور
اس کے ذریعے لوگ سروئسز میں آجاتے
ہیں۔ مولانا صاحب نے بہت وضاحت
سے کہہ دیا ہے۔ میں اس کو دہرائی نہیں
چاہتا۔ لیکن ان زبانوں کو اس سے نکال
کر باقاعدہ یہ سازش کی گئی ہے کہ ایک
مخصوص کمیونٹی کے لوگ جو ان زبانوں
کو ذرا زیادہ پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ سروئسز
میں نہ آئیں۔ یہ ایک سازش ہے اور
میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیق کریں
اور ان زبانوں کو اس کے اندر واپس لے کر
آئیں اور اس کے اندر اختیاری مضامین
کی اجازت دی جائے۔

[] Transliteration in Arabic Script.

श्री रफीक आलम (बिहार) : यह अफसोस और सदमा की बात है कि हमारे अपने ही मुल्क में हमारे लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे हम लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। यह जुवानें चाहे परशियन हो या अरबी हो या पाली हो उनका पंडित जवाहर लाल नेहरू के टाईम में एडिशन हुआ था, यह नहीं कि आज या कल हुआ है। इतने दिनों से यह जुवानें यूनिन पब्लिक सर्विस कमीशन में थी और आज जो लोग मुताबस्तिब हैं वे चाहते हैं कि मुसलमानों को, मैक्लीयरली कहना चाहता हूं कि वे मुसलमानों को किस तरह से नौकरी से निकाला जाए, वे यूनिन पब्लिक सर्विस कमीशन में न आए, किसी सूत्र से आई० ए० एस०, आई० पी० एस० से इनको अलहदा रखा जाए। यह बहुत साजिश के तहत काम हो रहा है। इसलिए मैं हुकुमत से आपके जरिए यह मांग करता हूं कि परशियन, अरबी और पाली यह हमारी तीनों जुवानें हैं, तीनों को रिस्टोर किया जाए और जखम पर ज्यादा नमक न छिड़की जाए।

[] Transliteration in Arabic Script.

شری رفیق عالم : یہ افسوس اور
 حسرت کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ہی
 ملک میں ہمارے لوگ کچھ ایسا کام کر
 جاتے ہیں جس سے ہم لوگوں کا سر شرم
 سے جھک جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب
 ہونے لگی ہو یا پالی ہونے لگی ہو
 کے نام میں اینٹیشن ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ
 آج یا کب ہو گا۔ اتنے دنوں سے یہ
 رابین لینین پبلک سروس کمیشن میں
 تھیں اور آج جو لوگ متعصب ہیں وہ
 چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو میں ٹیکہ لگا کر
 چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کس طرح سے
 نوکری سے نکالا جائے۔ وہ لینین پبلک
 سروس کمیشن میں نہ آئیں کسی صورت
 سے آئی۔ اسے اس آئی پی ایس سے ملو
 علیحدہ رکھا جائے۔ یہ بہت سازش کے
 تحت کام ہو رہا ہے۔ اس لئے میں حکومت
 سے آپ کے ذریعے یہ مانگ کرتا ہوں کہ
 پرشین عربی اور پالی یہ ہماری تینوں زبانیں
 ہیں۔ تینوں کو رستور کیا جائے اور زخم
 پر زیادہ نمک نہ چھڑکی جائے۔

श्री मोहम्मद खलोलुर रहमान : (आन्ध्र प्रदेश) : मौलाना आज़मी ने जो स्पेशल मेशन किया है, मैं उसकी भरपूर टाईद करता हूं और हुक़्मते हिन्द से मुतालिबा करता हूं कि जो परशियन, अरबी और पाली हिन्दुस्तान की इंतहाई जुवाने हैं और ताज़ुब तो इस बात का है कि हमारी अहम

जुबानों को किस तरह से यू० पी० एस० सी० ने खारिज किया है। मैं आपके तबसुत से हुक्मते हिन्द से यह मुतालिबा करता हूँ कि फौरी यह अपने अहकामात अगर हैं तो वापिस लें और इन जुबानों को बहाल करें।

شری محمد خلیل الرحمن : مولانا غلطی نے جو اسپیشل مینشن کیا ہے میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پیشینہ عربی اور پالی ہندوستان کی انتہائی زبانیں ہیں اور تعجب تو اس بات کا ہے کہ ہماری اہم زبانوں کو کس طرح سے یو۔ پی۔ ایس۔ سی نے خارج کیا ہے۔ میں اپنے توسط سے حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری وہ اپنے احکامات اگر ہیں تو واپس لیں اور ان زبانوں کو بحال کریں۔

प्रो० आई० जं० सनवी (कर्नाटक) : उपसभाध्यक्ष महोदय, परशियन, अरबी और पाली जुबानों के साथ जो सौतेली मां का व्यवहार हो रहा है, यह सहा नहीं जाता है। भाषा जो होती है वह तिसा एक समाज की धरोहर नहीं है यह पूरा दुनिया की है। इसलिए सच्ची भाषाएं, अच्छी भाषाएं जो क्लासिकल भाषाएं कहलाती हैं इन तीनों भाषाओं के जज्बात वे भी यहां पर पेश की हैं, मैं उनसे सम्बद्ध करते हुए अपने विचार प्रगट करता हूँ।

श्री सौहृदमव अमीन (पश्चिमी बंगाल) : पूरे हाऊस के जज्बात एक ही रहे हैं। मेरा मुतालिबा यह है कि हुक्मत इसकी छातबीन

करे कि किन लोगों ने इसको काटा है। वह ताजिश है। कर्मेटी की जो सिफारिश है वह चार जुबानों के मुतालिब है, तीन जुबानों को इसमें खत्म कर दिया गया। इसलिए मौलाना ने जो कुछ कहा मैं पूरी तरह से एसोशिएट करता हूँ।

شری محمد امین : پورے ہاؤس کے جذبات ایک ہی تھے ہیں میرا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت اس کی چیجان بین کرے کہ کن لوگوں نے اس کو کاٹا ہے۔ یہ سرائش ہے۔ کمیٹی کی جو سفارش ہے وہ چار زبانوں سے متعلق ہے۔ تین زبانوں کو اس میں ختم کر دیا گیا۔ اس لئے مولانا نے جو کچھ کہا میں پوری طرح سے ایسوسی ایٹ کرتا ہوں۔

श्री एस० एस० अहलुवालिया : (बिहार) मौलाना साहब ने जो मसला उठाया है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ और उनके समर्थन में सरकार से यह मांग करता हूँ कि परशियन, अरबी और पाली भाषा को जो यू० पी० एस० सी० के कोर्स से निकाली गई है, यह सरासर एक अन्याय है और यह वाकई खोजबीन करने की जरूरत है कि किन हालातों में यह पहले तो इंकलूड क्यों की गई और इंकलूड करने के पीछे क्या कोई कारण था और जब इंकलूड की गई तो आज निकालने के पीछे क्या कारण हैं? वह खोजबीन करने की जरूरत है, तथा जो लोग इसमें हैं उन पर सब्ब से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।

[श्री एस० एस० अहलुवालिया]

और सिर्फ यही नहीं स्टेट्स के प्रति, पी० ए० सी०, कारपोरेशन हर जगह वहाँ पर वहाँ की भाषाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह बिहार में मैथली भाषा को निकाल दिया गया। तो इस तरह से इस पर गौर करने की जरूरत है और सरकार को खुले दिल से इसमें खोजबीन करने की जरूरत है।

डा० फागुनी राम (बिहार) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भी चाहता हूँ कि आजमी साहेब ने जो प्रस्ताव किया है, जो मेशन किया है उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं और उनके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूँ। क्योंकि इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा है और धार्मिक लोगों का, धार्मिक ग्रंथों का उनके सेंटिमेंट्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसको पाने वाले लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए अरबी, फारसी और पाली भाषा को यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन में जनकल्याण के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए शामिल किया जाए, इस बारे में मैं पूर्णतया उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : I associate myself with the sentiments expressed by Maulana Obaidullah Khan Azmi Saheb. Arabic language is a common language and it is being learnt by students in various schools and colleges in this country. Now if an option is given to the candidates for answering their question papers in the UPSC examination in their own

mother tongue or in the language which they learn, it will be a better experience for them and they would be able to secure good marks. I do not know the reason given by the Government for removing these languages, that is Arabic, Persian and Pali from the UPSC examination. I would submit that it will hurt the sentiments of the people, especially the minorities, who are living in this country. Many people are learning and studying Arabic, Persian and Pali languages in this country and, therefore, removal of these languages from being used in the UPSC examination is totally unwarranted. I support Azmi Saheb on this count.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal) : Sir, I also associate myself with the sentiments expressed by Azmi Saheb.

उपसभाध्यक्ष (श्री संयद सिन्ने रजी) :

भाषाएँ और जुबानें हमारी मिलीजुली संस्कृति की गमाची करती हैं, तर्जुमानी करती हैं। ऑनरेबल मेम्बरान ने जिन जज्बात का इजहार किया है, मैं भी उससे अपने को एसोसिएट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बात की छानबीन करेगी कि किन-किन हालात में और किस वजह से इन तीनों बहुत ही दोलतमंद जुबानों को, अरबी, फारसी और पाली, इनको किस तरह से यूनिजन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात से निकाल दिया गया।

ایسا سچا ادھیکش (شہری سٹیڈ
 سبسطہ رضی): بھاشائیں اور زبانیں ہمارے
 ملی جلی سنسکرتی کی غمازی کرتی ہیں۔
 ترجمانی کرتی ہیں۔ آئرن سیل نمبر ان نے جن
 جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میں بھی اس سے
 اپنے کو ایسوسی ایٹ کرتا ہوں اور امید
 کرتا ہوں کہ سرکار اس بات کی چھان بین
 کرے گی کہ کن کن حالات میں اور کس
 وجہ سے ان تینوں بہت ہی دولت مند
 زبانوں کو۔ عربی۔ فارسی اور پالی ان کو کس
 طرح سے یو پی پبلک سروس کمیشن کے
 امتحانات سے نکال دیا گیا۔

[Transliteration in Arabic Script.

The House stands adjourned till 11.00
 A.M. on Thursday.

The House then adjourned at
 eight minutes past six of the
 clock till eleven of the clock on
 Thursday, the 3rd December,
 1992.